



2026:AHC:33225

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 8623/2024

संजय कुमार सिंह

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: जनार्दन यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

साथ में:

रिट ए संख्या 8633/2024,

रिट ए संख्या 8172/2025 और

रिट ए संख्या 8163/2025

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. आज दाखिल किए गए प्रत्युत्तर शपथ-पत्रों को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. मुख्य और संबंधित रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव, तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
3. चूंकि निजी पक्षों के बीच प्रति-शपथ-पत्र और प्रत्युत्तर-शपथ-पत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है और वे कोई और शपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए रिट याचिकाओं का निर्णय इसी प्रारंभिक चरण पर किया जा रहा है।
4. मुख्य रिट याचिका के तथ्य यह हैं कि रिट याचिकाकर्ता 20.03.2001 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था और 31.05.2019 को उसे सेवामुक्त कर दिया गया; इसके बाद, 19.10.2018 को सिविल पुलिस में रिक्त पद का विज्ञापन जारी किया गया। लिखित परीक्षा 27/28.01.2019 को आयोजित की गई थी। परिणाम 20.11.2020 को घोषित किए गए थे। शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन 23.11.2019 से 28.01.2020 तक आयोजित किया गया था, और रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका चयन 02.03.2020 को हुआ था और उसे 09.06.2021 को कांस्टेबल के पद पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। तथापि, मुख्य रिट याचिका में दिनांक 15.02.2023 के आक्षेपित आदेश के आधार पर, एक सेना कर्मी के रूप में की गई सेवा को शामिल करने के प्रयोजन हेतु वेतन सुरक्षा से इनकार कर दिया गया है।
5. जहां तक संबंधित सी1 रिट याचिका का संबंध है, तथ्य लगभग समान हैं, सिवाय तारीखों में बदलाव के; इसमें रिट याचिकाकर्ता को 03.08.2002 को भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती किया गया था, और 31.08.2019 को सेवामुक्त कर दिया गया। उसने 19.10.2018 को कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया। उसका चयन 02.03.2020 को हुआ, उसे 09.06.2021 को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, और 15.02.2023 को उसका वेतन संरक्षण समाप्त कर दिया गया।
6. संबंधित सी2 रिट याचिका के संबंध में, यहाँ भी रिट याचिकाकर्ताओं की संख्या नौ है। उनका नामांकन 04.07.1999, 12.01.1998, 15.02.2000, 06.03.2002, 04.04.2002, 22.03.2002, 05.02.2000 और 05.09.1999 को हुआ था। उन्हें 30.11.2018, 30.06.2016, 31.11.2017, 31.03.2019, 30.04.2019, 31.09.2018, 28.02.2017 और 30.11.2017 को सेवामुक्त कर दिया गया था, और उसके बाद उन्होंने पुलिस कांस्टेबल के चयन में भाग लिया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, हालाँकि 29.03.2023 को उनके वेतन संरक्षण को समाप्त कर दिया गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. इसी प्रकार, जहाँ तक संबंधित सी3 रिट याचिका का संबंध है, यहाँ रिट याचिकाकर्ता तीन हैं, जो 26.06.1996, 29.04.1994 और 16.06.2001 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और 31.03.2018, 01.05.2018 और 31.03.2019 को सेवामुक्त हुए थे; और उनका चयन पुलिस सेवाओं में हो गया था। 21.04.2025 के आदेश द्वारा उनके वेतन संरक्षण को निरस्त कर दिया गया था।
8. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि जिन आधारों पर प्रत्यर्थियों ने दावे को खारिज किया था—यानी यह तथ्य कि रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 23.12.2020 के सरकारी आदेश जारी होने के बाद हुई थी, और इसलिए वे वेतन सुरक्षा के हकदार नहीं हैं—वह आधार गलत और संदर्भ से बाहर है; विशेष रूप से तब, जब रिट-ए **10689/2024** (सीता राम शर्मा एवं **13** अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं **3** अन्य) में एक समन्वय पीठ ने, 09.04.2025 को तय की गई संबंधित रिट याचिकाओं के साथ, उक्त वर्गीकरण को कानून के अनुसार नहीं माना था—जिसके विरुद्ध दायर एक अंतर-न्यायालय अपील, विशेष अपील संख्या **1233/2025** (उत्तर प्रदेश राज्य एवं **3** अन्य बनाम विनय एवं **3** अन्य) को, संबंधित अपीलों के साथ, 15.12.2025 को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि पुलिस कांस्टेबलों को किसी विशेष बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजना प्रत्यर्थियों का दायित्व है—जो समय-समय पर बदल सकता है—और जिसके लिए रिट याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
9. दूसरी ओर, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अब उक्त मुद्दा रेस इंटीग्र नहीं रह गया है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा सीता राम शर्मा एवं **13** अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में इसका निर्णय पहले ही किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि एक विशेष अपीलीय पीठ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य एवं **3** अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में की गई है। उनका निवेदन है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को वापस संबंधित प्राधिकारी के पास भेज दिया जाए, ताकि वे निर्णय के आलोक में एक नया आदेश पारित कर सकें।
10. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।
11. तथ्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता सैनिक थे—यानी पूर्व-सैनिक—जिन्होंने सेवा-मुक्ति के बाद चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उन्हें पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया, यद्यपि उन्हें प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग बैचों में भेजा गया था। तथापि, प्रत्यर्थियों द्वारा अपनाए गए उक्त रुख को एक समन्वय पीठ द्वारा सीता राम शर्मा एवं **13** अन्य (पूर्वोक्त) मामले में खारिज कर दिया गया है, जिसमें निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:

“1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई उपरोक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से, वे याचिकाकर्ता—जिन्हें 30प्र0 सिविल पुलिस 2018 में कांस्टेबल जीडी के पद के लिए चुना गया था—प्रत्यर्थियों द्वारा अपनाए गए भेदभावपूर्ण रवैये से व्यथित हैं; यह रवैया उन्हें, पूर्व-सैनिकों के रूप में उनके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर वेतन सुरक्षा प्रदान न करने के संबंध में है। सभी याचिकाकर्ताओं का चयन और नियुक्ति पूर्व-सैनिकों की श्रेणी में हुई थी, और वे यह निवेदन करते हैं कि यदि उसी चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए चार अलग-अलग बैचों में अलग-अलग समय पर भेजा जाता है, तो राज्य सरकार का यह कदम उचित नहीं है कि वह प्रशिक्षुओं के पहले बैच को तो वेतन सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन अन्य प्रशिक्षुओं को इससे वंचित कर दे; और ऐसा करने का एकमात्र आधार यह हो कि एक सरकारी आदेश के तहत, बाद की किसी तारीख से पूर्व-सैनिकों को वेतन सुरक्षा न देने का निर्णय लिया गया था।

3. यह तर्क दिया गया है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना था; परंतु उस समय कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए, 30प्र0 पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2020 के आदेश के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को चार बैचों में विभाजित कर दिया, ताकि उन्हें अलग-अलग तिथियों पर और अलग-अलग अवधियों के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सके। पहला बैच अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था; दूसरा बैच मार्च 2021 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था; तीसरा बैच अक्टूबर 2021 में छह महीने के

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था; और अंतिम तथा चौथा बैच मई 2022 में छह महीने के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था।

4. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें प्रशिक्षण के दूसरे बैच में भेजा गया था, जो मार्च 2021 में शुरू हुआ और सितंबर 2021 तक, यानी छह महीने तक चला। जब पहला बैच अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहा था, तो उनके संबंध में नियुक्ति आदेश 23 दिसंबर, 2020 के सरकारी आदेश से पहले ही जारी कर दिया गया था—जिस तारीख को वह सरकारी आदेश जारी हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अब उन चयनित उम्मीदवारों को कोई वेतन सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, जो पूर्व-सैनिक हैं। सरकारी आदेश में आगे यह भी प्रावधान किया गया था कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकारी आदेश का संबंधित पैराग्राफ, जो पैराग्राफ 22 में निहित है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

- (1) सेना से सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनर्योजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।
- (2) ऐसे पुनर्योजित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय है, का वेतन पुनर्योजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।
- (3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षणीय नहीं है, उनमें पुनर्योजन पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु
 - (i) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।
 - (ii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्योजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।
 - (iii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अन्तिम वेतन से अधिक है, तो वेतनमान निर्धारण पुनर्योजन के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा।उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षणीय नहीं है, घटा दिया जायेगा।

राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

- (4) उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरुद्घटित (रीओपेन) नहीं किये जायेंगे।”

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि जनवरी, 2021 में पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, उन्हें वेतन सुरक्षा प्रदान की गई थी; उदाहरण के तौर पर, नव-चयनित कांस्टेबल कुलदीप सिंह पीएनओ संख्या 202641386 के वेतन निर्धारण से संबंधित दिनांक 24 जनवरी, 2024 का दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि पहले बैच को लाभ दिए जाने के बाद, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच में चुने गए उम्मीदवारों को, जो पूर्व सैन्यकर्मी भी थे, यह लाभ नहीं दिया गया।

6. उपरोक्त दलीलें रिट याचिका के पैराग्राफ 14 में उठाई गई हैं, जिसमें उन विभिन्न अन्य कांस्टेबलों का विवरण दिया गया है जिन्हें अंतिम वेतन सुरक्षा का लाभ मिला था, और जिन्होंने पूर्व-सैनिक होने के आधार पर इसकी मांग की थी। पैराग्राफ 14 के जवाब में दिए गए प्रति-शपथ पत्र के पैराग्राफ 16 में, यह बात इस प्रकार कही गई है:

“रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 14 की बातें इस हद तक स्वीकार की जाती हैं कि 11.10.2020 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल कुलदीप सिंह पीएनओ संख्या 202641386 की नियुक्ति के

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समय, 26.8.1977 और 18.5.1983 के सरकारी आदेश प्रभावी थे। वर्तमान में, राज्य सरकार की सेवा में पूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में 23.12.2020 का सरकारी आदेश प्रभावी है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा; अर्थात्, पूर्व सैनिकों के वे मामले इस आदेश के अंतर्गत आएंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार की सेवाओं में सरकारी आदेश जारी होने की तारीख को या उसके बाद हुई है।”

7. जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, प्रति-शपथ पत्र के पैराग्राफ 14 में किए गए कथनों को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि कुलदीप सिंह को यद्यपि पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, तथापि उसे 11.10.2020 को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था, जब दिनांक 26.8.1977 और 18.5.1983 के सरकारी आदेश प्रभावी थे; और इसलिए उसे वेतन संरक्षण का यह लाभ प्रदान किया गया। तथापि, पूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में दिनांक 23.12.2020 के सरकारी आदेश के लागू होने के परिणामस्वरूप, उन्हें उनके पिछले संस्थान के वेतन संरक्षण का हकदार नहीं माना गया; अतः वर्तमान याचिकाकर्ता को ऐसा कोई भी लाभ प्रदान नहीं किया जा सका। अतः, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं का वेतन सुरक्षा से केवल इस आधार पर वंचित किया गया है कि उनका प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के प्रथम बैच के बाद पूर्ण हुआ था; यद्यपि याचिकाकर्ता भी प्रथम बैच की ही भाँति प्रशिक्षु थे, जो बाद में कांस्टेबल बन गए। अतः, सभी नियुक्त व्यक्तियों का चयन वर्ष 2018 में आयोजित चयन एवं भर्ती प्रक्रिया के अनुसार किया गया था, और इसलिए उन्होंने वेतन समानता का दावा किया।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सरकारी आदेश के तहत लिए गए उस रुख का बचाव करने का प्रयास किया है, जिसमें वेतन सुरक्षा देने से इनकार किया गया था; इसके लिए उन्होंने भारत संघ बनाम अनिल प्रसाद 2022 5 एससीसी 461 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को वेतन सुरक्षा का लाभ देने से इनकार करने वाले केंद्र सरकार के नियमों को सही ठहराया गया था। अतः यह निवेदन है कि सरकार द्वारा वेतन सुरक्षा लाभ देने से इनकार करने की कार्यवाही में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती, जिससे उसे विकृत, भेदभावपूर्ण या मनमाना माना जा सके। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्णय के पैराग्राफ 4.5 पर भरोसा किया है, जो इस प्रकार है:

“5.4 इसलिए, सरकारी सेवा में प्रत्यर्थी का वेतन निर्धारण सीसीएस आदेश 1986 के पैरा 8 के बिल्कुल अनुरूप था। पैरा 8 में यह प्रावधान नहीं है कि सरकारी सेवाओं में पुनर्नियुक्ति पर, सशस्त्र बलों का कोई सेवानिवृत्त कर्मी अपनी मूल वेतन को अपने अंतिम आहरित वेतन के बराबर निर्धारित किए जाने का हकदार होगा। ऐसा मानना सीसीएस आदेश के पैरा 8 का उल्लंघन होगा। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी और फैसला करके एक गंभीर त्रुटि की है कि सरकारी सेवा में पुनः नियुक्त होने पर सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को, सशस्त्र बल कर्मियों के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन का अधिकार होगा। अतः, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, सीसीएस आदेश, 1986 के पैरा 8 के विपरीत होने के कारण, कायम रखने योग्य नहीं है।”

9. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इस याचिका में, सरकारी आदेश में निहित उस प्रासंगिक प्रावधान को चुनौती देने के बजाय—जो पूर्व-सैनिकों को सरकारी गैर-रक्षा प्रतिष्ठानों में पुनः-रोज़गार प्राप्त करते समय वेतन सुरक्षा का लाभ देने से इनकार करता है—याचिकाकर्ताओं के साथ हो रहे भेदभाव को ही अधिक चुनौती दी गई है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2024 0 एससी 764 मामले में दिए गए फैसले पर जोर दिया है, और यह तर्क दिया है कि केवल इस आधार पर कि काउंसिलिंग नहीं हुई या उसमें देरी हो गई, उन शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था, जो एक ही चयन प्रक्रिया के तहत समान और एक जैसी स्थिति में थे। उन्होंने निर्णय के पैराग्राफ 15 पर भरोसा जताया है, जो इस प्रकार है:

“अपीलकर्ता का मामला राकेश गौर (पूर्वोक्त) के मामले से अधिक मिलता-जुलता था, जिसने 05.11.2009 को प्रवेश लिया था। इस मामले के विशेष तथ्यों के आधार पर हमारी यह स्पष्ट

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राय है कि खण्ड न्यायापीठ ने इस मामले के तथ्यों पर अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त) और राकेश गौर (पूर्वोक्त) के निर्णयों में दिए गए तर्क को लागू करने के बजाय, दिनेश चंद्र दामोर (पूर्वोक्त) के मामले को लागू करके त्रुटि की है। जैसा कि अंकुल सिंघल (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया था, शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए प्रवेश पाने वाले छात्रों के एक समरूप समूह के बीच आपस में भेदभाव करना अनुचित होगा। जैसा कि उसमें बताया गया था, ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसलिंग के पहले राउंड में एडमिशन पाने वाले छात्र—भले ही उनके ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक हों—तो भी वे योग्य माने जाएँ, जबकि काउंसलिंग के बाद के राउंड में एडमिशन पाने वाले अन्य छात्र योग्य न माने जाएँ। इसी तर्क के आधार पर राकेश गौर (पूर्वोक्त) को अनुतोष दिए गए थे। राकेश गौर (पूर्वोक्त) का मामला अपीलकर्ता के मामले के बिल्कुल समान था। जो नियम एक पर लागू होता है, वही दूसरे पर भी लागू होना चाहिए।”

11. अतः, इस याचिका में इस न्यायालय द्वारा जिस एकमात्र प्रश्न का निर्धारण किया जाना है, वह यह है कि क्या उसी चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए उन उम्मीदवारों को दी गई वेतन सुरक्षा से याचिकाकर्ताओं को वंचित किया जा सकता है—जिन्हें पहले प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था—जबकि याचिकाकर्ताओं ने बाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया; और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण प्रशिक्षण का आयोजन चार अलग-अलग बैचों में किया जा रहा था। प्रत्यर्थियों की ओर से इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वे सभी याचिकाकर्ता, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए दूसरे बैच में भेजा गया था और बाद में उसी विज्ञापन के तहत, उसी चयन प्रक्रिया के माध्यम से 30 प्र0 पुलिस में कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए चुना गया था। यह प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के उद्देश्य से संपन्न किया जाता है; और एक बार उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद, अंततः प्रकाशित एवं घोषित चयन सूची में उसके नाम पर विचार किए जाने के परिणामस्वरूप ही यह प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। इस प्रकार, एक बार जब नियुक्ति के उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने वाले उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार हो गई, तो उसके बाद चयन का कोई भी चरण शेष नहीं रह गया था। इसलिए, चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति देना इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, अतः, न्यायालय की सुविचारित राय में, यदि प्रत्यर्थियों ने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षुओं को विभिन्न समूहों और वर्गों में विभाजित करने का निर्णय लिया, ताकि उन्हें अलग-अलग तिथियों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सके, और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर ऐसे प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गई, तो सेवा-संबंधी लाभों—जैसे कि वेतनमान, भत्ते और अन्य परिलब्धियाँ जो संबंधित पद के लिए अनुमेय हैं—के मामले में उनके साथ निश्चित रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठता के मामले में भी, केवल चयनित सूची का ही पालन किया जाना है। मनीलाल (पूर्वोक्त) के मामले में उद्धृत निर्णय याचिकाकर्ताओं के मामले पर पूरी तरह से लागू होता है। उस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी समरूप समूह के सदस्यों के बीच आपसी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, एक ही चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए सभी अभ्यर्थी एक समरूप समूह का निर्माण करेंगे, और उनकी नियुक्ति केवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक परिणामी परिणाम है—बशर्ते कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अस्वीकृत न कर दिया जाए। एक बार जब किसी समरूप समूह को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

12. प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले क्लस्टर या समूहों के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि समान स्थिति वाले कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यह एक उचित वर्गीकरण नहीं माना जाएगा। समानता का एक सुस्थापित नियम यह है कि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, और समान स्थिति वाले लोगों के साथ वेतन-समानता तथा सेवा-लाभों के मामले में समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

13. फिरंगी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2011) 2 यूपीएलबीईसी 987 के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि नियुक्ति पत्र जारी करने में नियुक्ति प्राधिकारी की त्रुटि के कारण, याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति में नहीं डाला जा सकता। हालाँकि यह मामला नियमितीकरण से संबंधित था, लेकिन चूँकि प्रबंधन ने नियुक्ति आदेश जारी करने में विलंब किया था—और वह भी नियमितीकरण नियमों की कट-ऑफ तिथि

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के बाद—इसलिए सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए उन्हें नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया गया। इस फैसले का पालन महेश नारायण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट ए संख्या 55606/2008) के मामले में भी किया गया है, जिसका निर्णय 19.12.2019 को आया था। इस मामले में, एक ही विज्ञापन के तहत चुने गए सभी आवेदकों को एक समान समूह माना गया, ताकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा सके। इसका कारण यह था कि विज्ञापन और चयन की प्रक्रिया पुरानी पेंशन योजना को खत्म किए जाने से पहले ही पूरी हो चुकी थी, भले ही नियुक्ति के आदेश बाद में जारी किए गए थे।

14. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ मुझे सरकारी आदेश के लागू होने के तरीके में—जहाँ तक पूर्व-सैनिकों को वेतन सुरक्षा से वंचित करने का प्रश्न है—कोई भी भेदभावपूर्ण बात नज़र नहीं आती, वहीं यह सरकारी आदेश केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा जिनमें उम्मीदवारों का चयन इस आदेश के जारी होने के बाद किया गया था। जिन सभी लोगों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, ताकि अंततः उन्हें नियुक्ति दी जा सके, वे एक समरूप समूह का निर्माण करेंगे; उन्हें वेतन सुरक्षा सहित ऐसे सभी लाभों का विशेषाधिकार प्राप्त होगा, और सरकारी आदेश से उनके दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. जहाँ तक विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय का प्रश्न है, उसमें प्रतिपादित विधि के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि मेरा भी यही मत है कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी आदेश को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे वर्तमान मामले पर लागू होने वाला माना जाना चाहिए।

16. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को अंतिम वेतन सुरक्षा का लाभ प्रदान करें, जैसा कि 30 प्र0 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के तहत प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिया गया था। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर, उचित आदेश पारित किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं को तदनुसारी लाभ प्रदान किया जाएगा।”

10. इसके अलावा इस न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष अपीलीय पीठ में, उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य (पूर्वोक्त) ने दिनांक 15.12.2025 को अपील खारिज कर दी है, जिसका आदेश नीचे उद्धृत है:

“1. सभी अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से, श्री तेज भानु पांडे, विद्वान स्थायी अधिवक्ता की सहायता से, श्री मनीष गायत, विद्वान अपर महाधिवक्ता को; तथा प्रत्यर्थियों की ओर से उनकी-अपनी अपीलों में, श्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और श्री आदित्य प्रकाश वर्मा, विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से, श्री आर.के. ओझा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना गया।

2. ये सभी अपीलें, माननीय एकल-न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.04.2025 को पारित एक साझा निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, यह निर्णय उन संबंधित रिट याचिकाओं के संबंध में दिया गया था, जिनका निस्तारण रिट ए संख्या 10689/2024 सीता राम शर्मा एवं 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य के साथ किया गया था जिसके तहत, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया, और अपीलकर्ता संख्या 3 (इस मामले में) को निर्देश दिया गया है कि वह याचिकाकर्ताओं को अंतिम वेतन सुरक्षा का लाभ प्रदान करे; क्योंकि 30 प्र0 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के पहले बैच को यह लाभ पहले ही दिया जा चुका है और उचित आदेश पारित किया जाएगा, तथा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों का परिणामी लाभ प्रदान किया जाएगा।

3. अपीलकर्ता, उत्तर प्रदेश राज्य ने इन सभी अपीलों में एक जैसा ही मुद्दा उठाया है, और इसलिए, इन सभी की सुनवाई एक साथ की गई और इन पर इस एक ही आदेश द्वारा निर्णय दिया जा रहा है। सभी अपीलों में शामिल मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों को, उनके नियुक्ति पत्रों की तारीख और उनके प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तारीख के आधार पर, एक अलग वर्ग के रूप में माना जा सकता है। प्रत्येक अपील में उम्मीदवारों से संबंधित तथ्यात्मक विवरण—जैसे कि उनकी पिछली सेवा का विवरण, नियुक्ति पत्र की तारीख, और उनके प्रशिक्षण अवधि के लिए पत्र में उल्लिखित तारीख—भिन्न हो सकते हैं।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. सुविधा के लिए, तथ्यात्मक विवरण स्पेशल अपील संख्या 1240/2025 से लिए जा रहे हैं, क्योंकि माननीय एकल-न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.04.2025 को पारित निर्णय और आदेश में यही मुख्य याचिका थी; तथापि, इस वर्तमान साझा आदेश का परिणाम सभी संबंधित मामलों पर लागू होगा। एकमात्र तथ्यात्मक अंतर संबंधित अपीलों में प्रत्यर्थियों/अभ्यर्थियों की संख्या का है।

5. विशेष अपील मामलों के इस समेकित समूह के अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात्, यह प्रतीत होता है कि इसमें सभी प्रत्यर्थी भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्य हैं, जो अलग-अलग समय पर विभिन्न रेजिमेंटों में भर्ती हुए थे। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रत्यर्थी को उसकी सेवा-अवधि पूरी होने पर सेवा-मुक्त अथवा सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उनकी व्यक्तिगत सेवा अवधियों में अंतर होने के बावजूद, इन मामलों में एक साझा तथ्य यह उभरकर सामने आता है कि सभी प्रत्यर्थियों ने अपनी सैन्य सेवा पूरी कर ली थी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनका चयन हुआ था, तथा उन्होंने उसी चयन सूची में अपना स्थान सुरक्षित किया था, जो इन अपीलों के समूह का विषय है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अक्टूबर 2018 की सीधी भर्ती के अनुसरण में तैयार की गई चयन सूची से नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो गई थी, क्योंकि प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने यह निवेदन किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, राज्य के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से आयोजित करना आवश्यक हो गया था; और इसलिए, उम्मीदवारों के संबंधित प्रशिक्षण चरणों के अनुरूप अलग-अलग तारीखों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया है कि 3000 पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने दिनांक 25.07.2020 के आदेश द्वारा, चयनित अभ्यर्थियों को अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग अवधियों में प्रशिक्षण हेतु चार बैचों में विभाजित किया। तत्पश्चात्, प्रथम बैच ने अगस्त 2020 में छह माह की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किया। दूसरा बैच मार्च 2021 में छह महीने के लिए शुरू हुआ। तीसरा बैच अक्टूबर 2021 में छह महीने के लिए शुरू हुआ, और चौथा बैच मई 2022 में शुरू हुआ, जो भी छह महीने की अवधि के लिए था।

7. विद्वान अपर महाधिवक्ता के अनुसार, राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहते हुए, अलग-अलग समय पर और अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग वेतन संरचना निर्धारित करने के लिए पूरी तरह अधिकृत था; और अपीलकर्ता राज्य अन्य बैचों के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने में भी पूरी तरह से न्यायसंगत था, भले ही उन्हें वह समान वेतन सुरक्षा प्रदान न की गई हो, जो पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले सदस्यों को दी गई थी। यह भी तर्क दिया है कि चयन सूची को सभी प्रयोजनों के लिए एक समरूप वर्ग नहीं माना जा सकता, और राज्य द्वारा बाद के तीन बैचों को पहले बैच से एक अलग स्थिति में रखना उचित है, क्योंकि पहले बैच ने अन्य बैचों की तुलना में अपना प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया था।

8. यह निर्विवाद है कि पहले बैच को, जिसने जनवरी 2021 में अपना प्रशिक्षण पूरा किया था, वेतन सुरक्षा का लाभ प्रदान किया गया था। विद्वान अपर महाधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि एक ही सूची से चयनित, अलग-अलग बैचों के उम्मीदवारों के साथ किया गया अलग व्यवहार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुमेय दायरे के अंतर्गत आता है; और इसलिए, राज्य को उन चार बैचों के लिए अलग-अलग वेतन संरचनाएँ निर्धारित करने का अधिकार है, जिन्होंने अलग-अलग समय पर अपना प्रशिक्षण शुरू किया था।

9. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के नियम 19 पर भरोसा जताया है, जिसे सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:

“नियम - 19. प्रशिक्षण।

(1) (क) नियम 15 और 16 के तहत कांस्टेबल के पदों के लिए अंततः चयनित उम्मीदवारों को, विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। बुनियादी प्रशिक्षण के

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दौरान कैडेटों पर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नियमावली के प्रावधान लागू होंगे। यदि बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसका चयन/अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।

(ख) बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण होने वाले कैडेटों की पुनः परीक्षा, पूरक प्रशिक्षण के पश्चात्, विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी। पूरक प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

2) नियम 17 के तहत पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को, विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा।

10. विद्वान अपर महाधिवक्ता का तर्क है कि कांस्टेबल के पद के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे विभाग के प्रमुख द्वारा निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसे उत्तीर्ण करें; ऐसा न कर पाने की स्थिति में, उनका चयन रद्द किया जा सकता है। यह तर्क दिया है कि यह नियम अधिकारियों को पूरक प्रशिक्षण और पुनः परीक्षा आयोजित करने का अधिकार भी देता है, और उन उम्मीदवारों की सेवाएँ समाप्त करने का भी, जो इसके बाद भी असफल रहते हैं; वहीं, पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों के लिए भी निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है, और इसलिए, जब तक प्रशिक्षण पूरा नहीं हो जाता, तब तक राज्य को वेतन संरचना में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क दिया है कि राज्य की कार्यवाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रत्यर्थियों का चयन 2018 में सिविल पुलिस और पीएसी में कांस्टेबल के पदों के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत किया गया था, और मार्च 2020 में घोषित परिणाम में उन्हें विधिवत रूप से भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में रखा गया था। वह आगे यह तर्क देते हैं कि 23.12.2020 का सरकारी आदेश—जिस हद तक यह प्रावधान करता है कि उक्त तिथि के बाद की गई सभी नियुक्तियाँ वेतन सुरक्षा की हकदार नहीं होंगी—अस्वीकार्य है; क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से तब, जब सभी उम्मीदवारों को एक ही चयन सूची में रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया है कि प्रथम चरण में नियुक्त अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा निरंतर स्वीकार किया गया है।

12. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता आगे मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 2024 एससी 4404 पर भरोसा जताया है, और यह तर्क किया है कि एक साझा चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए सभी उम्मीदवार एक ही समरूप समूह का हिस्सा होंगे, और इस समरूप समूह के भीतर आपस में किया गया भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट ए संख्या 55606/2008, जिसका निर्णय इस उच्च न्यायालय द्वारा 19.12.2019 को किया गया था, पर भी भरोसा किया है। उपर्युक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देते हैं कि इस प्रकार का विशिष्ट व्यवहार केवल किसी बोधगम्य विभेदक आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है, जो इन मामलों के तथ्यों में विद्यमान नहीं है।

13. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रशिक्षण के संबंध में विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का उत्तर दिया है, अर्थात् 30प्र0 पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियमावली, 2015 का नियम 19। उनके अनुसार, विद्वान एकल-न्यायाधीश ने यह सही ही टिप्पणी की है कि प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों के लिए एक प्रक्रिया मात्र है, और एक बार जब नियुक्ति के उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने वाले उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार हो गई, तो चयन का कोई और चरण शेष नहीं रह गया था। उन्होंने आगे 30प्र0 पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियमावली, 2015 के नियम 18 पर भरोसा किया है, जिसे आसान संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



“नियम - 18. नियुक्ति।

(1) नियम 15 और 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों के नामों को उसी क्रम में लेकर नियुक्ति करेगा, जिस क्रम में वे नियम 15 के खंड (छ) के अधीन तैयार की गई सूची में हैं। नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा, जिसमें यह निर्देश होगा कि वे पत्र जारी होने की तारीख के एक महीने के भीतर, या नियुक्ति पत्र में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किसी अन्य तारीख को, सेवा/प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करें। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसका चयन/नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति, जिसे इन नियमों के लागू होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त किया गया हो और जो उस पद पर कार्यरत हो, उसे इस नियमावली के अधीन स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा।

(2) यदि नियम 17 के अधीन किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किए जाते हैं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम वरिष्ठता क्रम में दिए जाएंगे, जैसा कि चयन में निर्धारित किया गया है, या, जैसा भी मामला हो, जिस कैडर से उन्हें पदोन्नत किया गया है, उसमें उनकी जो स्थिति थी।

बशर्ते कि इस नियमावली के लागू होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को, इन नियमों के तहत स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा, और ऐसी स्थायी नियुक्ति को इन नियमों के तहत की गई नियुक्ति माना जाएगा।

14. उपर्युक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क दिया है कि नियम 18 के अंतर्गत, नियम 15 और 16 के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है, और केवल उसके बाद ही नियम 19 के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना अपेक्षित है। प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि नियमावली की योजना से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण से पहले जारी किया जाता है; अतः प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का एक भाग नहीं माना जा सकता, जैसा कि विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा सही ही अभिनिर्धारित किया गया है, क्योंकि प्रशिक्षण नियुक्ति के उपरान्त ही आयोजित किया जाना है।

15. हमने अपीलकर्ताओं/राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता, दोनों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का अवलोकन किया है, जिसमें विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष भी शामिल हैं। कुछ बुनियादी तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। सभी उम्मीदवारों का चयन—चाहे उन्हें बाद में प्रशिक्षण के लिए किसी भी बैच में भेजा गया हो—अक्टूबर 2018 में जारी किए गए उसी भर्ती विज्ञापन के आधार पर किया गया था। चयन सूची सामान्य थी, चयन प्रक्रिया एकसमान थी, और नियुक्तियाँ उसी भर्ती प्रक्रिया से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई थीं।

16. अभिलेखों के साधारण अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सभी नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2018 की उसी सीधी भर्ती के तहत की गई नियुक्तियों से संबंधित हैं, जो एक ही विज्ञापन और चयन प्रक्रिया से उत्पन्न हुई थीं। किसी भी पक्ष का यह भी दावा नहीं है कि जिस विज्ञापन के आधार पर चयन सूची तैयार की गई थी, उसमें किसी ऐसे वर्गीकरण या श्रेणी-वार अंतर का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, राज्य यह भी सिद्ध नहीं कर पाया है कि प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले उम्मीदवारों को चार अलग-अलग चरणों में विभाजित करना किसी तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित था।

17. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा सुविचारित मत है कि चरणों में आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण की आवश्यकता केवल अपीलकर्ता राज्य के समक्ष मौजूद बुनियादी ढाँचे की सीमाओं और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपात स्थितियों के कारण पड़ी थी, न कि चयनित सूची में शामिल उम्मीदवारों के बीच किसी भी प्रकार के तर्कसंगत अंतर के कारण। अतः, बाद के बैचों में

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रशिक्षण के लिए रखे गए उम्मीदवारों को वंचित करना सरासर मनमाना है और इसमें पक्षपातपूर्ण भेदभाव का दोष निहित है।

18. माननीय अपर महाधिवक्ता के तर्क का संपूर्ण आधार यह है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण ने स्वयं ही चार अलग-अलग श्रेणियाँ निर्मित कर दीं, जिससे राज्य को अलग-अलग वेतन संरचनाएँ निर्धारित करने तथा उन प्रत्यर्थियों को वेतन सुरक्षा प्रदान करने से वंचित रखने का अवसर प्राप्त हो गया, जो बाद के बैचों का हिस्सा थे।

19. यद्यपि यह न्यायालय महामारी से संबंधित आपात स्थितियों और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को स्वीकार करता है, तथापि ऐसी बाहरी और अस्थायी प्रशासनिक विवशताएँ एक ही वर्ग के उम्मीदवारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को उचित नहीं ठहरा सकतीं। अनुच्छेद 14 के तहत अनुमेय वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाली कानूनी स्थिति इतनी सुस्थापित है कि उसे विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है; और जब सुस्थापित मापदंडों पर इसकी जाँच की जाती है, तो अपीलकर्ता राज्य द्वारा प्रस्तुत औचित्य जाँच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

20. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 एससीसी 1 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित अथवा भ्रामक नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, वर्गीकरण एक समझने योग्य अंतर पर आधारित होना चाहिए; क्योंकि अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को मनमाने भेदभाव से बचाना है—चाहे वह भेदभाव किसी कानून के स्पष्ट प्रावधानों के कारण हो, या फिर उस कानून के अनुचित प्रयोग के कारण। किसी भी वर्गीकरण का आधार एक ऐसा बोधगम्य अंतर होना चाहिए जिसका, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तार्किक संबंध हो; ऐसा न होने पर, ऐसा वर्गीकरण एक अस्वीकार्य भेदभाव का रूप ले लेता है।

21. डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1990) 2 एससीसी 715 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो उम्मीदवार एक ही भर्ती अधिसूचना और चयन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, वे सेवा लाभों के उद्देश्य से एक ही वर्ग का गठन करते हैं। वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि एक बार जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति नियमों के अनुसार किसी पद पर हो जाती है, तो उसकी वरिष्ठता की गणना उसकी नियुक्ति की तिथि से की जानी चाहिए, न कि उसकी पुष्टि की तिथि से। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, प्रशिक्षण की पूर्णता को उन उम्मीदवारों के बीच एक उप-वर्ग बनाने के लिए विचारणीय बिंदु नहीं माना जा सकता, जिन्हें एक ही चयन सूची में रखा गया है।

22. अपीलकर्ताओं ने किसी ऐसे सांविधिक नियम की ओर संकेत नहीं किया है, जो राज्य को वेतन निर्धारण या वेतन संरक्षण के प्रयोजनार्थ किसी चयन सूची के भीतर उप-श्रेणियाँ निर्मित करने के लिए अधिकृत करता हो। दरअसल, राज्य का अपना पक्ष यह है कि प्रशिक्षण के लिए चरणबद्ध रूप से भेजे जाने का कदम पूरी तरह से प्रशासनिक आवश्यकता के कारण उठाया गया था। प्रशासनिक आवश्यकता, भले ही वह सद्भावपूर्ण हो, को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संवैधानिक रूप से अनुमेय विभेदक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस तरह के कदम की अनुमति देने से राज्य को मनमानी या आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर एकसमान अधिकारों को खंडित करने का अवसर मिल जाएगा—एक ऐसी प्रथा जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार अस्वीकृत किया है।

23. इसलिए, विद्वान एकल-न्यायाधीश का यह निष्कर्ष सही था कि प्रत्यर्थियों और अन्य समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को—जिनका चयन अक्टूबर 2018 की उसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था—वेतन सुरक्षा और सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता, जो प्रशिक्षण के लिए पहले भेजे गए उम्मीदवारों के पहले बैच को प्रदान किए गए थे। संवैधानिक मानकों के स्वतंत्र अनुप्रयोग पर, हमें विद्वान एकल-न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



24. ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर, हमारा यह मत है कि अपीलकर्ता राज्य द्वारा एक ही चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों के बीच, केवल उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने की तारीखों के आधार पर किया गया भेदभाव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए एक अस्वीकार्य वर्गीकरण है।

25. राज्य द्वारा पहले बैच को दी गई वेतन सुरक्षा और उससे जुड़ी वेतन संरचना का लाभ, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच के उन उम्मीदवारों से नहीं छीना जा सकता, जो उसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे और जिन्हें उसी चयन सूची में शामिल किया गया था।

26. इसलिए, हमें विद्वान एकल-न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता। तदनुसार, विशेष अपीलों का यह समूह असफल रहता है और इसे खारिज किया जाता है। माननीय एकल-न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थियों और अन्य सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों को वेतन सुरक्षा और परिणामी लाभ प्रदान करने के संबंध में जारी निर्देश की पुष्टि की जाती है। राज्य इस आदेश की तिथि से बारह सप्ताह के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

27. यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निस्तारण किया जाता है।”

11. चूंकि विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, उनके मुचकिल से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, उपर्युक्त मध्यवर्ती तथ्यों के आलोक में इस मामले पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है।

12. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित तरीके से निर्णय लिया जा रहा है:

(क). पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा दिनांक 20.07.2023 को पारित आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

(ख). यह मामला वापस भेजा जाता है, ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप एक नया आदेश पारित किया जा सके।”

12. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित रीति से किया जा रहा है:

(क). पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 15.02.2023, 29.03.2023 और 21.04.2025 को पारित विवादित आदेश निरस्त किए जाते हैं।

(ख). यह मामला वापस भेज दिया जाता है, ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप एक नया आदेश पारित किया जा सके।

13. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”